

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 581/2024

दिनेश सिंह नेहरा

—अपीलार्थी

बनाम

- संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर।
- डॉ. मदनलाल गहनोलिया, ब्लॉक पशु स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर, सीकर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 18.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पुनिया, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

- मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
- अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पटवार कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थागण संख्या 4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी की माताजी का वर्ष 1997 में देहांत हो चुका है और उसके पिता ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है तथा अपीलार्थी की पत्नी मल्टीपल गठिया से पीड़ित है जिनकी देखभाल एवं सुश्रुषा हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी की पुत्री जिसकी वर्तमान में सैकेण्डरी की परीक्षाएँ चल रही हैं तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 400 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन जिले में 21 पद रिक्त हैं, उसके बावजूद बिना किसी आधार एवं

शिकायत तथा बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।

- 3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
- 4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
- 5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का

स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

- 6 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

*"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी को समंजित किए जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

- 7 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

*"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

- 8 अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 400 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

- 9 हम प्रस्तुत अपील में जारी आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना या प्रस्तुत नियमों का उल्लंघन नहीं पाते हैं।
10. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य